also the apex bodies of these subsidiaries, as it seems, are not really inclined to place orders on M.A.M.C. As a result, the industry is unable to make full utilization of its capacity. As you are aware, the Government of India have had a clear formulation for purchase and price preference in respect of placement of orders from one public sector to another public sector. This policy is also not being pursued in its real sprit.

I have already requested the Energy Minister regarding placement of orders for Madhuban Coal Washery under SCCL on MAMC, because the order amounting to Rs. 60 crores is being placed on private/foreign firm though MAMC was the lowest tenderer. I again like to mention that the order for coal handling plant for vindhyachal Projcet under NIPC valued at Rs. 30 crores, was initally placed under a private scetor comany, ignoring the claim and reasonableness of MAMC ; and when MAMC protested, the customer awarded the contract to another public sector unit, who has no expertise in this field.

If this sort of a situation is thrust upon MAMC , it will not only effect the existance of MAMC. adversely, but will also cause an erosion into the already built-up infrastructure in this Durgapur belt, including the small scale and ancillary innustries, as no further industry has been set up by Government of India in this belt for the last 20 years.

So, I urge upon the concerned Minister to take approiate steps.

(xvii) Scarcity of Vanaspati in the country

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, देश के विभिन्न भागों विशेषकर दिल्ली में वनस्पति घी की भारी कमी पैदा हो गई है । खाद एवम नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कमी निकटभविष्य में दूर होने वाली नहीं है क्योंकि वनस्पति घी बनाने वाली मिलों को कच्चा माल और आयातित खाने का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उत्पादन में कमी होने की वजह से बाजार में भी माल कम सप्लाई किया जा रहा है । आम जनता की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह वनस्सपति निर्माताओं को निर्देश दे कि वे सरकार द्वारा नामांकित ऐजेन्सियों जैसे सुपर बाजार, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन और कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज आदि को ही माल सप्लाई करने में वीरयता दें और जो व्यापारी जखीरेबाजी तथा ब्लैक करने के दोषी पाये जाएं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायें ।

(xviii) Demand for an Express Train between Delhi and Sikar (Rajastan) vis Lohare.

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से सीकर व झुन्झुनू (राजस्थान) के निवासी सीकर से दिल्ली वाया लुहारू एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं । मैंने भी कई बार सदन में बहस के दौरान सीकर-दिल्ली रेलगाड़ी चलाने की मांग रखी । इस समय सीमर से दिल्ली के लिए एक कोच पहला व दूसरा दर्जा का व एक कोच दूसरा दर्जा तीन टीयर शयन का उत्तर रेलवे 91, पश्चिम रेलवे 28 में लगाये जाते हैं । ये काफी नहीं हैं, इनमें भेड़बकरी की तरह मुसाफिर घुसते हैं और सोना तो दूर रहा, खड़े-खड़े भी दिल्ली आना कठिन होता है । जिनको इन डिब्बों में जगह नहीं मिलती उन्हें लुहारू जंक्शन पर आधी रात